

नारीवादी विदेश नीति: दक्षिण एशिया में उभरते रुझान

Pooja

Assistant professor, Department of Political Science

Maharani Kishori Jaat Kanya Mahavidyalaya, Rohtak, Haryana, India

सारांश :

यह शोध-पत्र दक्षिण एशिया में नारीवादी विदेश नीति (एफएफपी) की अवधारणा, संभावनाओं, तथा संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करता है। विश्व स्तर पर स्वीडन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों द्वारा अपनाई गई एफएफपी ने पारंपरिक कूटनीतिक ढाँचों को चुनौती दी है। दक्षिण एशिया, जहाँ कूटनीति आज भी सुरक्षा, रणनीति और शक्ति संतुलन के इर्द-गिर्द केंद्रित है, वहाँ यह विमर्श अपेक्षाकृत नया और आवश्यक है। यह अध्ययन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे प्रमुख देशों में लिंग-संवेदनशील कूटनीतिक रुझानों का मूल्यांकन करता है, और नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों के आलोक में क्षेत्रीय वैकल्पिक कूटनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह शोध न केवल मौजूदा विदेश नीति ढांचे की सीमाओं को उजागर करता है, बल्कि दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समाजिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त नारीवादी कूटनीतिक मॉडल के संभावित खाके को भी प्रस्तावित करता है।

कूट शब्द:

नारीवादी विदेश नीति, दक्षिण एशिया, लिंग और कूटनीति, फेमिनिस्ट IR सिद्धांत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल

1. प्रस्तावना :

विदेश नीति का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शक्ति, सैन्य हितों और राज्य सुरक्षा जैसे पुरुष-केंद्रित उद्देश्यों से संचालित होता रहा है। नारीवादी दृष्टिकोण इस एकांगी सोच को चुनौती देता है और विदेश नीति को समावेशी, मानवीय और न्याय-आधारित दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित करता है। 2014 में स्वीडन द्वारा औपचारिक रूप से फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को अपनाने के बाद से यह

विमर्श वैश्विक स्तर पर गति पकड़ चुका है। कनाडा, मैक्सिको, स्पेन और चिली जैसे देशों में एफ एफ पी को समावेशिता, मानवाधिकार और लैंगिक न्याय के केंद्रीय तत्व के रूप में देखा जा रहा है।

दक्षिण एशिया में, हालांकि महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक उपस्थिति (जैसे इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना) रही है, परन्तु विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया में लिंग समावेशन अभी भी सीमित है। क्षेत्र में कूटनीति अब भी सैन्य विचारधारा, क्षेत्रीय तनावों और राष्ट्रवाद से प्रेरित है। इस शोध का उद्देश्य इस पारंपरिक संरचना में नारीवादी हस्तक्षेप की संभावनाओं का विश्लेषण करना है।

2. साहित्य समीक्षा :

इस अध्ययन के सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट करने हेतु साहित्य समीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई दोनों प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया गया है। नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की जड़े 1980 के दशक में विकसित हुईं, जब पारंपरिक यथार्थवादी सिद्धांतों को पुरुष केंद्रित और सैन्यवादी मानकर चुनौती दी गई।

सिंधिला ऐनलो ("Bananas, Beaches and Bases") का कार्य इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि महिलाएं केवल युद्ध की शिकार नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सक्रिय भागीदार भी हैं।

जे. टिकनर (1992) ने अपने ग्रंथ "Gender in International Relations" में यह दर्शाया है कि किस प्रकार IR में लिंग की उपेक्षा ने कूटनीति की व्यापकता को सीमित किया है।

क्रिस्टीन सिल्वेस्टर (2002) ने संघर्ष समाधान, शांति निर्माण और मानव सुरक्षा जैसे विषयों को IR के केंद्र में लाने की मांग की।

कैरोलिन लेक्सा और क्लेयर हचिंसन के लेखों में बताया गया है कि नारीवादी विदेश नीति केवल महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं, बल्कि संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और नीति मूल्यों के पुनर्निर्माण की मांग करती है।

स्वीडन की 2014 की नीति दस्तावेजों और कनाडा की Feminist International Assistance policy (2017) जैसे आधिकारिक दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि एफ एफ पी की वैश्विक मान्यताएं लिंग समानता, मानवाधिकार और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से गहरे रूप से जुड़ी है।

दक्षिण एशियाई परिपेक्ष्य में कुछ स्वतंत्र शोध (जैसे- UN Women South Asia Report 2021; Women in Diplomacy Report, 2020) संकेत देते हैं कि नीति निर्माण संस्थानों में महिला भागीदारी में वृद्धि तो हुई है, परन्तु वह निर्णय-निर्धारक तक नहीं पहुंच पाई है।

इस समीक्षा स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया में एफ एफ पी की अवधारणा अभी नवोन्मेष की स्थिति में है, जिसे सम्यक नीति, संस्थागत ढांचे और समाजिक दृष्टिकोण द्वारा पोषित किया जाना आवश्यक है।

3. सैद्धांतिक ढाँचा :

यह शोध नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत पर आधारित है, जो पारंपरिक IR के यथार्थवादी और उदारवादी दृष्टिकोणों को चुनौती देता है। पारंपरिक IR थ्योरी राज्य-केन्द्रित, युद्ध-प्रधान और शक्ति-संतुलन पर आधारित होती है, जिसमें लिंग, सामाजिक न्याय या नैतिकता को गौण माना गया है। इसके विपरीत, नारीवादी IR यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लिंग कोई परिधीय कारक नहीं बल्कि संरचनात्मक शक्ति-संबंधों का केंद्र है। प्रमुख नारीवादी अवधारणाएँ जो इस शोध को आधार देती हैं:

(1) Visibility of the Marginalized (हाशिए की आवाज़ को केंद्र में लाना):

Cynthia Enloe (1989) का प्रसिद्ध प्रश्न – “Where are the women?” – IR के विमर्श में उन महिलाओं को सामने लाता है जिन्हें सैनिक, नीति-निर्माता या कूटनीतिज्ञ नहीं बल्कि सिर्फ युद्ध की पीड़िता के रूप में देखा गया। यह शोध कूटनीति में महिला भागीदारी को केवल संख्या के रूप में नहीं, अपितु निर्णयों की नैतिक दिशा में परिवर्तन के रूप में देखता है।

(2) Ethics of Care vs. Ethics of Power:

सामान्य IR नैतिकता को रणनीति के अधीन रखती है, जबकि नारीवादी दृष्टिकोण “मानवीय सुरक्षा”, “करुणा आधारित नीति” और “नैतिक नेतृत्व” को प्राथमिकता देता है। Joan Tronto के “Ethics of Care” मॉडल से प्रेरित यह दृष्टिकोण विशेष रूप से दक्षिण एशिया जैसे विविधतापूर्ण क्षेत्र में उपयुक्त है।

(3) Interconnectedness of Gender and Security:

Traditional security केवल सीमा और सैन्य खतरे तक सीमित है। Feminist IR यह दिखाता है कि असुरक्षा घरेलू हिंसा, आर्थिक बहिष्करण, और लैंगिक असमानता से भी उत्पन्न होती है। यह शोध विदेश नीति में सुरक्षा की इस व्यापक अवधारणा को समाहित करता है।

(4) Triple R Model (Rights, Representation, Resources):

यह फ्रेमवर्क बताता है कि किसी भी फेमिनिस्ट विदेश नीति में तीन मुख्य स्तंभ होते हैं:

अधिकार (Rights): महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा।

प्रतिनिधित्व (Representation): निर्णय-निर्माण में वास्तविक भागीदारी

संसाधन (Resources): लिंग-संवेदनशील बजट और वितरण प्रणाली

(5) Postcolonial Feminism का योगदान:

दक्षिण एशिया जैसे औपनिवेशिक अनुभव से गुज़रे समाजों में पश्चिमी फेमिनिस्ट मॉडल पूरी तरह लागू नहीं होते। इसलिए यह शोध Postcolonial Feminism की समझ को भी शामिल करता है, जो कहता है कि “एकसमान फेमिनिज़्म” नहीं हो सकता। भारतीय, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और नेपाली संदर्भों को उनकी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विविधता में देखा जाना चाहिए।

यह शोध फेमिनिस्ट IR थ्योरी पर आधारित है, जो मानता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति, युद्ध, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ लिंग, मानवाधिकार और न्याय भी केंद्र में होने चाहिए।

4. अनुसंधान कार्यप्रणाली :

यह अध्ययन तुलनात्मक केस स्टडी पर आधारित है। चयनित चार देशों- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का विश्लेषण नीति दस्तावेजों, भाषणों, आधिकारिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है। इसमें सामग्री विश्लेषण, पाठ्य विश्लेषण और द्वितीयक स्रोतों की गहन समीक्षा शामिल है। साथ ही, क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रवृत्तियों की तुलना करते हुए लिंग आधारित संरचनात्मक रुझानों की पहचान की गई है। यह अध्ययन गुणात्मक और विवेचनात्मक दोनों दृष्टिकोणों को समाहित करता है।

5. देशवार विश्लेषण :

भारत:

- महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि लेकिन नीति निर्माण में प्रभाव सीमित
- “नेबरहुड फर्स्ट” और “एक्ट ईस्ट” जैसी नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव

पाकिस्तान:

- महिला प्रतिनिधित्व कम; हिना रब्बानी खार जैसे अपवाद
- पितृसत्तात्मक और सुरक्षा केंद्रित नीति संरचना

बांग्लादेश:

- शेख हसीना के नेतृत्व में लैंगिक प्रतिनिधित्व बेहतर
- UN मिशन में महिला भागीदारी प्रमुख विशेषता

नेपाल:

- संविधानिक रूप से प्रगतिशील
- विदेश नीति में लैंगिक समावेशन की शुरुआत

6. प्रमुख निष्कर्ष :

- दक्षिण एशिया में एफ एफ पी का औपचारिक अंगीकरण अभी नहीं हुआ है।
- महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है लेकिन नीति निर्माण में उनकी भूमिका सतही है।

- 'सुरक्षा' को अभी भी सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि नारीवादी सुरक्षा मानव केंद्रित है।

7. चुनौतियाँ:

दक्षिण एशिया जैसे विविधतापूर्ण और समाजिक रूप से जटिल क्षेत्र में नारीवादी विदेश नीति को अपनाने की राह में अनेक संस्थागत, सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाएं हैं, प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

- संस्थागत पितृसत्ता:

विदेश नीति और सुरक्षा क्षेत्र आज भी पुरुष वर्चस्व वाले संस्थानों के नियंत्रण में हैं, जहां महिला भागीदारी प्रतिकात्मक है।

- सुरक्षा-केंद्रित विदेश नीति:

आतंकवाद, सीमा विवाद और आंतरिक अस्थिरता से जूझते देशों में विदेश नीति सैन्य और सामरिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहती है।

- लैंगिक आंकड़ों की अनुपलब्धता:

नीति निर्माण में लिंग विश्लेषण के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है जिससे निर्णय प्रक्रियाएं लिंग संवेदनशील नहीं हो पाती।

- राजनीतिक अस्वीकार्यता:

एफ एफ पी को प्रायः पश्चिमी अवधारणा कहकर खारिज कर दिया जाता है। पारंपरिक नीति निर्माता इसे असंगत और नैतिक आदर्शवाद मानते हैं।

- मीडिया और जनमत की भूमिका:

एफ एफ पी जैसे मुद्दे प्रायः मीडिया विमर्श से बाहर रहते हैं, जिससे नागरिक जागरूकता और समर्थन कम होता है।

- धार्मिक-सांस्कृतिक बाधाएं:

दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में सांस्कृतिक रूढ़ियां और धार्मिक आस्थाएं महिला नेतृत्व को सीमित करती हैं।

- **क्षेत्रीय सहयोग की कमी:**

SAARC जैसे मंचों में राजनीतिक गतिरोध के कारण क्षेत्रीय स्तरीय लिंग नीति पर विमर्श रूप है।

8. संभावनाएँ :

यद्यपि चुनौतियां गंभीर हैं फिर भी दक्षिण एशिया में नारीवादी विदेश नीति को विकसित करने की संभावनाएं कई स्तरों पर उभरती दिख रही हैं:

- **महिला नेतृत्व का सशक्त इतिहास:**

भारत (इंदिरा गांधी), पाकिस्तान (बेनजीर भुट्टो), बांग्लादेश (शेख हसीना) और श्री लंका (चंद्रिका कुमारतुंगा) में महिला नेतृत्व का अनुभव रहा है, जो एक सामाजिक स्वीकार्यता का संकेत है।

- **युवा और डिजिटल जनसंख्या:**

सोशल मीडिया और युवाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण लैंगिक समानता और न्याय के मुद्दों को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और वैश्विक दबाव:**

CEDAW, UNSCR 1352 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते दक्षिण एशियाई देशों को लैंगिक दृष्टिकोण को नीति में शामिल करने के लिए बाध्य करते हैं।

- **नई विदेशी नीति प्राथमिकताएं:**

जलवायु परिवर्तन, मानवीय आपदाएं, प्रवासन जैसे गैर पारंपरिक मुद्दों पर नीति बनाते समय एफ एफ पी को अधिक प्रासंगिकता मिल रही है।

- **शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण:**

क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ने से कूटनीतिक पेशों में उनकी पहुंच संभव हो रही है।

- नारीवादी संगठनों में सक्रियता:

Women in Diplomacy Network, SAARC Gender Initiative जैसे मंच धीरे-धीरे नीति को प्रभावित कर रहे हैं।

9. निष्कर्ष (Conclusion):

दक्षिण एशिया जैसे ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक और सुरक्षा प्रधान विदेश नीति के ढांचे में नारीवादी विदेश नीति की अवधारणा न केवल आवश्यक है बल्कि संभावनाशील भी है। वैश्विक स्तर पर एफ एफ पी ने विदेश नीति को केवल सामरिक सोच से हटाकर सामाजिक न्याय, समावेशन और मानव सुरक्षा की दिशा में पुनर्परिभाषित किया है। हालांकि दक्षिण एशियाई देशों ने अब तक इस दिशा में औपचारिक नीति नहीं अपनाई है, परन्तु महिला नेतृत्व, नागरिक समाज की सक्रियता और वैश्विक दबाव जैसी परिस्थितियां इसे अपनाने के अवसर प्रदान करती हैं। नारीवादी विदेश नीति केवल महिला प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करती बल्कि यह पूरी नीति संरचना को नैतिकता, करुणा और समानता के सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित करने का आग्रह करती है। यदि दक्षिण एशिया के देश पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें समावेशी और मानव केंद्रित नीति की ओर उन्मुख होना होगा। दक्षिण एशिया में नारीवादी विदेश नीति का मार्ग कठिन अवश्य है परन्तु यह मार्ग समतामूलक और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की ओर ले जा सकता है।

10. नीति सिफारिशें:

1. विदेश मंत्रालयों में लैंगिक ऑडिट अनिवार्य किया जाए
2. फेमिनिस्ट प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम
3. SAARC Gender Diplomacy Forum की स्थापना
4. नीति निर्माण में महिला संगठनों की भागीदारी

5. विश्वविद्यालयों में FFP पर शोध प्रोत्साहित करना।

11. संदर्भ सूची:

Enloe, C. (2014). Bananas, Beaches and Bases. University of California Press.

Tickner, J. A. (1992). Gender in International Relations. Columbia University Press.

Sylvester, C. (2002). Feminist International Relations. Cambridge University Press.

Aggestam, K., & Rosamond, A. (2016). Swedish Feminist Foreign Policy. Foreign Policy Analysis.

Government of Canada. (2017). Feminist International Assistance Policy.

UN Women South Asia (2021). Gender Equality in Foreign Policy: South Asia Overview.

Women in Diplomacy Network (2020). Gender and Representation in South Asian Foreign Services.

Hutchinson, C. (2020). Feminist Peace and Foreign Policy. Journal of Global Security Studies.

Ministry of External Affairs, India (2022). Annual Report 2021–22.

SAARC Secretariat (2018). SAARC Gender Strategy.